ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

याद आते हैं पर्यावरण प्रेमी स्व. केशव लाल महतो

रविवारीय, 05 - 11 अप्रैल 2020 वर्ष- एक, अंक-35, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

लंबी हुई कोरोना से लड़ाई

मुख्य संवाददाता

रांची : जीती हुई जंग कैसे मुश्किल में डाली जाती है? इसका जीता जागता उदाहरण हम भारतीयों ने पेश किया है। स्वास्थ्य सेवाओं में नीचले पायदान पर रहने वाले भारत ने कोरोना पर तकरीबन नियंत्रण पा लिया था। कथित तीसरे चरण में भी देश में महज 1100 मरीज थे। और रोज औसतन 50 के करीब कोरोना के मरीज मिल रहे थे। इस दरम्यान ऐसा भी हुआ था कि दिल्ली और यूपी में नये मरीजों के मिलने की संख्या में कमी आनी शुरू हो गयी थी और देश के चैतन्य नागरिक अब ये उम्मीद करने लगे थे कि भारत आसानी से कोरोना पर काबू पा लेगा? लेकिन अप्रैल की शुरूआत ने जैसे सोये जिन्न को जगा दिया। सभी राज्यों में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढने लगी और महज दो दिन में ही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दुगुनी हो गयी ।1100 के आस पास स्थिर मरीजों की संख्या दो हजार पार हो गयी। झारखंड जैसे बचे हुये राज्य में भी कोरोना संक्रमित लोग मिलने लगे। और महज एक सप्ताह पहले जहां प्रतिदिन 30 - 40 नये मरीज मिल रहे थे आज उसकी संख्या चार सौ से छह सौ प्रतिदिन है। ऐसे में कोरोना पर लगभग काबू पा चुकेभारत के लिये ये जंग मुश्किल होती जा रही है।

क्यों बिगड़ रही है स्थिति?

लॉकडाउन में लापरवाही, लाखों मजदूरों के शहरों से अपने गांवों कस्बों की ओर पलायन से नये संक्रमण की स्थिति बनी लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मानें तो सबसे खतरनाक और कोरोना को प्रत्येक राज्यों में पहुंचाने का काम तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने किया। सरकारी आकड़ों में ये बात कही जा रही है कि देश के तकरीबन सभी प्रमुख राज्यों से दिल्ली में तबलीग के कार्यक्रम में तीन हजार से ज्यादा लोग शामिल हुये और जब ये सभी वापस अपने राज्यों में लौटे तो कोरोना को फैलाने के मुख्य कारक बने। एक आंकड़े के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या का 33 प्रतिशत सिर्फ तबलीग से जुड़े लोगों की है। अब दिल्ली में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढती ही जा रही है वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी एक सप्ताह में हीं दुगुनी हो गयी है। इन सबके अलावा सरकार और डॉक्टरों के सामने एक दुसरी समस्या भी सामने आ रही है कि संदिग्ध मरीज सहयोग करने के बजाय छुपते फिर रहे हैं, क्वारेंटीन होने से मना कर रहे हैं। और कोरोना संक्रमित इलाके के लोग मेडिकल टीम पर एकजुट होकर हमले कर रहे हैं। डॉक्टरों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की वारदातें बढी हैं। भारत में कुछेक लोगों का असहयोग और उनकी धार्मिक सोंच ने कोरोना से इस संघर्ष को और कठिन बना दिया है।

झारखंड के लोग किसी खुशफहमी में न रहें

देश के सभी बड़े राज्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद भी झारखंड में लंबे समय तक इसका एक भी मरीज नहीं मिला था। और राज्यवासी मन ही मन चैन की सांस ले रहे थे। और सोशल मीडिया में झारखंड के कोरोना से अछूता रहने पर तरह-तरह के पोस्ट कर रहे थे। लेकिन पिछले सप्ताह रांची के हिदपीढी में मलेशियाई महिला के कोरोना संक्रमण की पुष्टि होते ही राज्यवासियों में भय का वातावरण बन गया। इसके बाद हजारीबाग और बोकारो में भी कोरोना पोजीटिव मरीज मिले और हिंदपीढी में दुसरे मरीज के मिलने से ये स्पष्ट हो गया कि झारखंड भी अन्य राज्यों की तरह ही खतरे में है। राज्य में लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी संख्या में मजदूर कामगार महानगरों से लौटे हैं और उन सबकी जांच नहीं हुई है, कुछ चोरी छुपे अपने गावों में जाकर छुप गये है। ऐसे में झारखंड में भी स्थिति बिगड़ जाये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

हजारीबाग में कोरोना संक्रमित मरीज बंगाल से लौटा था और उसकी तबियत खराब होने पर जब जांच की गयी तो वह कोरोना संक्रमित पाया गया, इस एक वाकये से हम समझ सकते हैं कि झारखंड में ऐसे संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत होगी?

भावुकता में मूर्खता न करें

झारखंड में कोरोना के इस संकट के मद्देनजर बहुत सारे लोग गरीबों, जानवरों और जरूरतमंदो की मदद कर रहे हैं। ये जरूरी भी है। कई लोग, संगठन, युवा समूह भोजन , राशन से लेकर सड़क पर घुमने वाले पशुओं, जानवरों को भी खाना खिला रहे हैं। इस दरम्यान गरीब गुरबों की मदद कर रहे हैं। यह एक सराहनीय कार्य है लेकिन इस काम में ज्यादा लापरवाही, भावुकता और मदद करते हुये फोटो खिंचवाने,सेल्फि लेने और उसे सोशल मीडिया में प्रचारित करने की होड़ भी लगी हुई है। चुंकि अब कोरोना से झारखंड भी अछूता नहीं रहा । यहां भी चार मरीज मिले हैं। ऐसे में आप का संक्रमित होना अन्य लोगों को भी कई प्रकार से संकट में डाल सकता है।

क्या संयोग से बचा हुआ है भारत?

यूरोप और अमेरिका से अगर हम तुलना करें तो भारत अब तक कोरेाना के संहार से बचा हुआ है। यहां अब तक सवा चार हजार मरीजों के अलावा तकरीबन सौ से कुछ अधिक मौतें हुई हैं। एक अरब से ज्यादा आबादी वाले अर्द्धविकसित देश में जहां एक बड़ी आबादी को पीने के लिये स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं वहां ये आंकड़े विश्व को चौकाने वाले हैं। पहले यूरोप और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में इसके फैलने पर भयंकर होने का अंदाजा लगाया था, लेकिन अब तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ का कहना है कि भारतीयों की कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता, सत्तर के दशक में दिये गये बीसीजी के टीके और समय पर किये गये देशव्यापी लॉकडाउन ने देश को बदतर स्थिति से बचा लिया। लेकिन कोई भी अब लापरवाही भारी पड़ेगी।

रेल कर्मचारियों के लिए टेली हेल्थ फैसेलिटीज

रांची : देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए रांची रेल मंडल ने हटिया स्थित मंडल अस्पताल को कोविड -19 अस्पताल में परिवर्तित कर दिया है तथा कोरोना संक्रमण से बचने हेतु सभी कर्मचारियों के लिए टेली हेल्थ फैसेलिटीज उपलब्ध कराई है यह सुविधा मंडल के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग तथा चिकित्सा विभाग के संयुक्त प्रयास से सम्भव हुआ है।रेल कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए मंडल द्वारा यह एक अनूठी पहल है।

रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें यह महसूस होता है कि स्वयं डॉक्टर के पास जाकर दिखाना अति आवश्यक है तो वह मंडल अस्पताल में जाकर डॉक्टर से अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन साधारण परिस्थिति में वे अपने घर पर ही रह कर उनको दिये गए रेलवे तथा लैंड लाइन नम्बर, स्काइप आई डी,स्काइप नेम के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा दिये गए मेल आई डी के माध्यम से सुबह 10 :00 बजे से 13 :30 बजे तक एवं 16 :00 बजे से 17 :30 बजे तक मंडल के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं तथा डॉक्टर के सलाह के अनुसार अस्पताल से दवा ले सकते हैं।

कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए सीसीएल ने जारी किया हेल्पलाईन नम्बर

रांची :सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कोविद 19 के खिलाफ लड़ाई में सीएमडी गोपाल सिंह के नेतृत्व में सीसीएल अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में सीसीएल ने अपना हेल्पलाईन नम्बर 0651-2365998/2365999/2361013/2360606 जारी किया है जिस पर सीसीएल कर्मियों के साथ-साथ सभी आमजन सम्पर्क कर सकते हैं। 'कोराना वायरस'' से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, बचाव, सुझाव एवं जानकारी को सीसीएल द्वारा जारी हेल्पलाईन नम्बर पर प्राप्त कर सकते हैं।

बीएयू ने कोरोना संकट में पशुपालकों को संक्रमण से बचाव का दिया सलाह

संवाददाता

रांची : कोरोना वायरस के कारण पशुपालन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद कहते है कि कोरोना मनुष्य से मनुष्य के बीच फैलता है. इसका मीट, मछली व अंडों आदि के संक्रमण से कोई लेना देना नहीं है. गलत अफवाहों के चलते उपभोक्ताओं के बीच भ्रम व पैनिक की स्थिति बनी हुई है. जिससे पशुपालन से जुड़े किसानों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है. प्रदेश की सरकार ने भी मीट, मछली व अंडों की बिक्री पर लगी रोक हटा ली है।विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी उद्योग विभाग ने भी इस बाबत एडवाइजरी जारी की है. कोरोना संकट का सामना करने के लिए पशुपालन क्षेत्र में भी बचाव के उपाय किए जाने की जरूरत बताई है. ताकि लोगों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से मुक्त पशु उत्पाद मिले.

पशु उत्पादों के उपभोग को लेकर भ्रम व पैनिक की स्थिति को दूर करने के लिए पशुपालकों को जागरूक किये जाने की जरूरत है. कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम को लेकर डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद ने पशुपालकों को कई सुझाव दिये है. उन्होंने पशुपालकों को स्वंय के अलावा पशु एवं पक्षियों की जैविक सुरक्षा करने की जरूरत बताई है. पशुपालकों को गाय, भेंस, बकरी, सूकर एवं मुर्गी आदि की देखभाल के समय

मुँह में मास्क लगाने और सेनेटाईजर या साबुन से प्रत्येक घंटे हाथ धोने की सलाह दी है. पशु फार्म में बाहरी लोंगो को प्रवेश नहीं करने देने तथा पशुओं के ठहरने के स्थल को सुबह और शाम फीनाईल से धोने की बात कही है. दुध दुहने से पहले और बाद में हाथों को सेनेटाईजर या साबुन से सेनेटाईज करने तथा दुध के थन को डीटॉल या साबुन के पानी से धोने को कहा.

उन्होंने पशुओं के घर या शेड में एक या दो आदमी से ही कार्य लेने तथा मरे पशुओं को तुरंत हटाकर कर अन्यत्र जमीन में गाड़ने तथा मृत पशुओं को कहीं बाहर नहीं फेंकने को कहा है। मुर्गीपालन से जुड़े लोगों को भी मुँह में मास्क लगाकर समय - समय पर हाथों को सेनेटाईज करने की आवश्यकता है. मुर्गीघर को एक - दो दिनों के अंतराल पर डिसइन्फेक्शन से बचाव हेतु बाजार में उपलब्ध दवा का छिड़काव करना जरूरी है. इसके अलावा समय - समय पर फ्यूमीगेशन करने की आवश्यकता है, ताकि उस स्थल को वायरस एवं बैक्टीरिया से मुक्त रखा जा सकें. फ्यूमीगेशन में 40 मि.ली. फारमेलीन और 20 मि.ली. पोटाशियम परमेगेनेट को मिट्टी के बर्तन में आधे घंटे छोड़ने के बाद इस्तेमाल करना चाहिये. पशुओं को झुण्ड में नहीं रखना चाहिये. नियमित अंतराल पर पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराये और पशुओं की बिक्री में ग्राहक से उचित दूरी बनाकर कर रखने की भी सलाह दी.

डॉ प्रसाद ने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य अवयव है. पशुपालकों को कोरोना संकट की घड़ी में अपने स्वस्थ्य की तरह पशुओं की भी देखभाल करने की आवश्यकता है।

अमेरिका के चीड़ियाघर में बाघिन हुई कोरोना से संक्रमित

जानवरों में भी हो रहा है कोरोना का संक्रमण?

एजेंसियां: अब तक ये माना जा रहा था कि जानवरों में कोरोना का संक्रमण नहीं होता है। लेकिन अमेरिका के चीड़ियाघर में एक बाघिन के शरी में इसके वायरस के पाये जाने से चिकित्साविज्ञानियों की चिंता बढ गयी है। हाल तक बताया जा रहा था कि चमगादड़ और पैंगानि से कोरोना का वायरस मनुष्यों में आया लेकिन खुद चमगादड़ और पैंगोलिन की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत होती है कि उनमें यह वायरस बेअसर पड़ा रहता है और किसी अन्य जानवरों में भी ये प्रभावी नहीं रहता। लेकिन अमेरिका मे बाघिन के कोरोना संक्रमण से जानकारों के माथे पर चिंता की नयी लकीरें उभर आयी हैं।

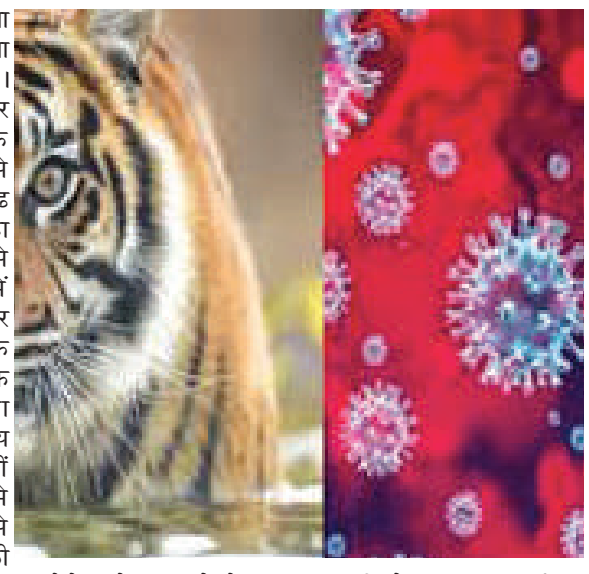

कोरोना से जानवरों में संक्रमण नहीं होता इस निष्कर्ष पर जल्दबाजी की गयी । अब फिर से इस पर शोध की जरूरत है। आखिर पशु पक्षियों से ही बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू के अलावा एड्स तक के मनुष्यों में आने का इतिहास है। अगर कोरोना का संक्रमण जानवरों और हमारे आस पास के पालतू पशु पक्षियों में भी हुआ तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और कठिन होती चली जायेगी। क्योंकि अब तक खुद को समझदार प्राणी कहने वाले मनुष्यों ने कई गलतियां की है और कोरोना को वैश्विक तौर पर फैलाया है ऐसे में जानवरों में इसका संक्रमण और बड़ी चुनौती होगी।

लॉकडाउन से वायुप्रदूषण अपने न्यूनतम स्तर पर

सुधीर शर्मा

रांचीः कोरोना वायरस के दहशत ने पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया है। खुद को सोशल कहने वाला समाज अब स्वयं के अस्तित्व की रक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा ले रहा है। रोज हजारों लोगों की मौत और डरावनी खबरों से भले ही आप चिंतित हो। इसी बीच एक अच्छी खबर यह है, कि दुनिया के शीर्ष प्रदूषित शहरों की सूची में आने वाले भारतीय शहर अब इस सूची से बाहर निकलकर लोगों को शुद्ध हवा दे रहे है। देशव्यापी 21 दिनों के लॉकडाउन के पहले ही दिन देश के प्रमुख शहरों के प्रदूषण के स्तर में काफी गिरावट देखने को मिला है। आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर में और भी गिरावट देखने को मिलेगा।

विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में गुरूग्राम का पहला स्थान आता है। हाल के दिनों में कोराना वायरस के बचाव के लिए जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण आज गुरूग्राम की जहरीली हवा शुद्धता के पैमाने को छू रही है। विगत एक महीने के आँकड़े देखे तो हम पाएंगे कि जहाँ 26 फरवरी को गुरूग्राम में एक्यूआई का लेवल 355 अर्थात खतरनाक स्थिति में था, वहीं 28 मार्च को लॉक-डाउन के चौथे दिन एक्यूआई 50 के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया।

पिछले एक महीने में गुरूग्राम के वातावरण में पीएम 2.5 वायुमण्डलीय कण के आँकड़ों को देखें तो हम पाएंगे, कि 26 फरवरी को यहां की हवाओं में पीएम 2.5 का स्तर 118 अर्थात खराब था, वहीं आज यह अप्रत्याशित रूप से कम 25 के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। पीएम 2.5 का यह स्तर न केवल इंसानों की सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी स्वास्थ्यवर्द्धक है।

देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, तो जहाँ की हवाओं में एक दिन

रहने का मतलब 10 सिगरेट पीने के बराबर हानिकारक माना जाता था। सरकार की ऑड-इवेन की कोशिशें भले ही कागजों पर प्रदूषण के स्तर को कम करती रही हो। आज जब पहियों की रफ्तार थम गई, तो वही जहरीली हवाएं सुरक्षित हो गई।

पिछले एक महीनों के प्रदूषण का हाल देखें तो भले ही एक्यूआई का स्तर 110 है, लेकिन दिल्ली की हवाओं में पीएम 2.5 वायुमण्डलीय कण की मात्रा 64 के स्तर को छू रही है, जो सामान्य दिनों से काफी कम है।

अपने वनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात झारखण्ड में भी कोरोना वायरस के कारण प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है। राज्य की राजधानी रांची में शोरगुल कम होने से अब दिन में भी पंछियों के चहकने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। राँची की हवाओं में वायुमंडलीय कण सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी कम 30 माइक्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी अच्छा है। वहीं झारखण्ड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर की बात करें, तो यहाँ का वायु प्रदूषणांक अन्य दिनों की अपेक्षा आधे से भी कम 54 के स्तर पर है। हवा में पीएम 2.5 की मात्रा सामान्य दिनों के मुकाबले अप्रत्याशित रूप से कम होकर 35 के न्यूनतम स्तर पर है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते है, कि हवा में धुलकणों की मात्रा में काफी कमी आई है। लॉकडाउन के कारण शहरों में गाड़ियां नहीं चल रही है, जिससे ध्वनि प्रदूषण का स्तर काफी कम है। शनिवार को जमशेदपुर में ध्वनि का स्तर 58.85 डेसीबल रिकॉर्ड किया गया।

राँची और जमशेदपुर के मुकाबले देश की कोयला राजधानी धनबाद की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, फिर भी अपने सामान्य दिनों की अपेक्षा में शनिवार को धनबाद में प्रदूषण अपने न्यूनतम स्तर पर है। वायु प्रदूषणांक अर्थात एक्यूआई की मात्रा जहाँ 79 है, वहीं पीएम 2.5 की मात्रा 58 रिकॉर्ड किया गया।

आत्म मंथन का समय

कोरोना के संकट से जूझते हुये विश्व को अब चार महिने हो गये। चीन से चला यह नासूर पूरे विश्व को संकट में डाले हुये है। यूरोप अमेरिका जैसे सक्षम देश इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। इटली, स्पेन की कौन कहे ब्रिटेन और अमेरिका जैसे सक्षम देशों में प्रतिदिन हजार से ऊपर हो रही मौतें अपने आप में चिंताजनक हैं। आखिर विज्ञान और भौतिक सुख साधनों के तरक्की के साथ ही उन्नत चिकित्सा विज्ञान भी क्यों कोरोना के सामने नीरीह है? हर रोज फलां देश ने वैक्सिन बनाया, फलां ने इसकी दवा खोज ली और फलां करने से कोरोना पर काबू पा सकते हैं जैसे भ्रामक खबरों में दुनिया राहत खोज रही है। लेकिन अब तक कहीं से भी राहत भरी कोई खबर नहीं मिली है। कोरोना की कोई दवा नही बन सकी है और यह अजेय है। ऐसी स्थिति में मानव जाति को ही यह मंथन करना पड़ेगा कि ऐसी नौबत क्यों आयी? अब तक की जानकारी के अनुसार यह वूहान के एक बाजार से फैला जहां कई प्रकार के जानवरों का मांस बेचा जाता है और कोरोना वायरस चमगादड़ या पैंगोलीन के मांस को खाने से मनुष्यों में आया और कहर बन कर फैलते चला गया। वहीं कुछ को कहना है कि ये मानव निर्मित वायरस है जो साजिश के तहत फैलाया गया वहीं कुछ का कहना है कि ये मानव निर्मित वायरस जानबूझ कर नहीं बल्कि दुर्घटनावश मनुष्यों में फैल गया। कारण जो भी हो लेकिन ये तो तय है कि ये मनुष्यों का अपना कुकर्म ही है।

कोरोना की महामारी ने मनुष्यों को उनकी औकात भी बता दी है। चार महिने के इसके व्यापक संहार के बाद भी अपनी ताकत पर इठलाने वाला मनुष्य इसकी दवा नहीं खोज पाया। हर रोज टीका और दवा खोजने की भ्रामक खबरें जरूर आ रही हैं। और कोरोना बगैर जाति धर्म अमीर गरीब देखे सबों को अपना ग्रास बना रहा है। लेकिन इन सबके बीच इस वायरस ने मनुष्यों को एक आत्ममंथन का मौका भी दिया है और वो ये कि क्या अपने सुख साधनों के लिये प्रकृति का व्यापक दोहन जरूरी है ?इस संकट के दौर में लोग कम सुख साधनों में भी जी रहे हैं और ये भविष्य के लिये भी एक संकेत है।

सिर्फ स्वाद के लिये किसी भी जीव को मार कर खा जाना या संहार के लिये खतरनाक जैविक हथियार के तौर पर वायरस का निर्माण? ये सब अंततः आज सारे मनुष्य जाति के लिये आत्मघाती साबित हो रहे हैं। न तो चीन इससे सुरक्षित रहा न अब अमेरिका और न ही यूरोप के समृद्ध देश। लेकिन इसकी सबसे भयंकर मार उन गरीब देशों पर पड़ रही है जो पहले से ही बुनियादी जरूरतों के लिये संघर्षरत थे और अब कोरोना की मार को सहना उनके लिये कठिन होता जा रहा है। आखिर सक्षम देशों के इस कृत्य ने सारे विश्व को संकट में डाल दिया।

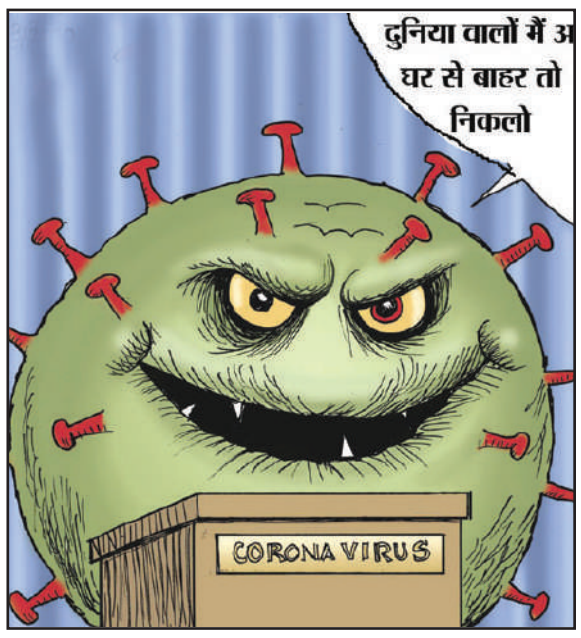

अमेरिका ऐसे बना कोरोना का सबसे बड़ा गढ़

अमेरिका में कोरोना विस्फोट की कई वजहें हैं, हालांकि कई जानकार आशंका जता रहे हैं कि सबसे बदतर स्थिति अभी आनी बाकी है। इस वक्त अमेरिका में इस वायरस के सबसे ज्यादा मामले हैं।

अमेरिका के लोग कितने चिंतित हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 मार्च को इंटरनेट में "रूरल प्रॉपर्टी" की सर्च पिछले साल की तुलना में 364 फीसदी ज्यादा बढ़ गई। नॉर्थ कैरोलाइना में ऐसी ही एक कंपनी चलाने वाले जॉन हेनेस कहते हैं कि कोरोना संकट ने लोगों को यह अहसास कराया कि उन्हें बहुत पहले ही इस तरह की प्रॉपर्टी में निवेश कर लेना चाहिए था। वे बताते हैं कि मार्च के मध्य तक वे इतनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं जितनी 2019 में पूरे साल में बेची थीं। हेनेस कहते हैं, "बहुत से लोग महीनों या शायद सालों से सोच रहे थे कि खरीदें या नहीं लेकिन इस वायरस ने उन्हें फैसला लेने पर मजबूर कर दिया।" वहीं जिन गांवों में घर खरीदे जा रहे हैं, वहां लोगों को अब डर सता रहा है कि उन्हें नए लोगों के साथ अपने संसाधन बांटने पड़ेंगे। अकसर ऐसी दूर दराज जगहों पर लोग निवेश के मकसद से घर खरीद कर रख लेते हैं और फिर साल में एक या दो बार वहां छुट्टी बिताने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कोरोना संकट के बीच हालात अलग होंगे। वैसे, इस अजीब ट्रेंड में अमेरिका अकेला नहीं है। कनाडा, यूरोप और न्यूजीलैंड में भी कई लोग इस तरह की "सर्वाइवल प्रॉपर्टी" में निवेश कर रहे हैं।

प्रकृति को चुनौती के नतीजे भुगतने होंगे

हमने दूसरे राष्ट्रों को मात देने के लिए बड़े-बड़े हथियार और बम बना लिए, दूसरे ग्रहों पर पहुंच गए, पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचने या खरीदारी करने का इंतजाम कर लिया, लेकिन विरोधाभास देखिए कि एक अतिसूक्ष्म वायरस से मुकाबला करने में अक्षम साबित हो रहे हैं।

ज्योति सिडाना

इतिहास बताता है कि मनुष्य प्रारंभ में अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए प्रकृति पर निर्भर था। खाना-पीना, पहनना, रहना सब कुछ उसे प्रकृति से ही मिलता था। जब तक मनुष्य ने प्रकृति के साथ संतुलन का रिश्ता बनाए रखा, प्रकृति ने उसका पोषण किया। लेकिन जैसे ही वह प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन करने लगा तो प्रकृति ने मनुष्य अस्तिव को चुनौती देना शुरू कर दिया। प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता उस दिन से ही बिगड़ना शुरू हो गया, जबसे मनुष्य में लालच की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई।भारत को शुरू से ही आध्यात्मिक परिवेश वाला देश माना जाता है, जहां प्रकृति यानी पेड़-पौधे, आकाश, धरती, जल, वायु, पशु-पक्षी सभी को पूजा जाता रहा है। ये सभी मनुष्य अस्तित्व को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि पृथ्वी हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पूरे संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं।

धीरे-धीरे सभ्यता और आधुनिक विकास के बाद मनुष्य ने प्रकृति पर नियंत्रण करना और उस पर अपनी निर्भरता को कम करना सीख लिया। जैसे वर्षा न होने पर कृत्रिम वर्षा करना, क्लोनिंग के माध्यम से नए जीव की उत्पत्ति, कृत्रिम तरीके से मनुष्य शिशु का जन्म, कृत्रिम मनुष्य अंगों का निर्माण, कृत्रिम ऊर्जा बनाना इत्यादि। उसे लगने लगा कि अब वह प्रकृति से अधिक शक्तिशाली हो गया है। उसने आकाश को फतह कर लिया, ब्रह्मांड के कोनों तक पहुंच चुका है। इसलिए अब उसे प्रकृति से डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने प्रकृति का आवश्यकता से अधिक दोहन करना शुरू कर दिया। जंगल के जंगल काट डाले, पहाड़ों को नष्ट कर दिया, नदियों और हवा को दूषित कर दिया, जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों को विलुप्तप्राय बना दिया। या कहें कि जीवन चक्र को ही बाधित कर दिया। परिणामस्वरूप प्रकृति ने समय-समय पर प्लेग, मलेरिया, चेचक, हैजा, खसरा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और अब कोरोना के रूप में न केवल मनुष्य अस्तिव को, बल्कि प्रत्येक जीव के अस्तिव को चुनौती दे डाली है। इतिहास साक्षी है कि इन महामारियों की वजह से हर बार अनगिनत मौतें हुईं, फसलें नष्ट हो गईं, कई सभ्यताएं समूल नष्ट हो गईं। आखिर क्यों?आज हर राष्ट्र महाशक्ति बनने की होड़ में लगा है। आधुनिक तकनीक का विकास करके वह अन्य राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। लेकिन ऐसा करते समय मनुष्य यह भूल गया है कि आज भी प्रकृति के अनेक पक्ष ऐसे हैं जिन पर से वह परदा नहीं उठा पाया है। सवाल है कि जो पक्ष अज्ञात है, जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की भूल कैसे की जा सकती है? ऐसा नहीं है कि यह सब अचानक हुआ है, अपितु समय-समय पर प्रकृति ने संकेत दिए।कभी जलवायु परिवर्तन के रूप में, कभी बाढ़, सूखा, भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में तो तो कभी महामारी के रूप में। लेकिन स्वयं को सर्व शक्तिशाली मानने के अहम में मनुष्य ने प्रकृति के इन संकेतों की हमेशा उपेक्षा की और परिणाम हमारे सामने हैं। आज हर चीज दूषित है। जल, वायु, फल, सब्जी, मसाले, अनाज और दवाएं कुछ भी तो शुद्ध नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमने हर चीज पर जीत हासिल कर ली है और बाकी पर जल्द ही कर लेंगे।

महाकवि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे, उसे ही काट रहे थे। तो क्या हम भी वैसा ही नहीं कर रहे हैं? यह जानते हुए भी कि धरती पर जीवन के लिए प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बना रहना आवश्यक है फिर भी इसे नष्ट करने पर आमादा हैं।आखिर मनुष्य क्या हासिल करना चाहता है, वह भी स्वयं को विनाश के कगार पर लाकर? स्टीवर्ट उद्दाल का तर्क है कि हवा और पानी को बचाने या जंगल और जानवर को बचाने वाली योजनाएं असल में मनुष्य को बचाने की योजनाएं हैं। इस स्थिति को भांपते हुए ही गांधीजी ने कहा था कि आधुनिक शहरी औद्योगिक सभ्यता में ही उसके विनाश के बीज नीहित हैं।प्रकृति ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया और हमने उनकी कीमत निर्धारित कर दी। उन्होंने सन् 1931 में लिखा था कि भौतिक सुख और आराम के साधनों के निर्माण और उनकी निरंतर खोज में लगे रहना ही अपने आप में एक बुराई है। यदि भारत ने विकास के लिए पश्चिमी मॉडल को अपनाया तो उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक अलग धरती की जरूरत होगी। आवश्यकता इस बात की है कि लालसा और आवश्यकता में अंतर स्थापित किया जाए। यह सच है कि जिंदगी के लिए सुविधाएं जुटाते-जुटाते हम भूल गए कि इसके कारण मनुष्य और प्रकृति के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा है।

मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति की ऐसी कोई वस्तु नहीं बची है, जिसे बाजार ने उपभोक्ता वस्तु या कहें कि क्रय-विक्रय की वस्तु में नहीं बदला। विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य जाति के एक हिस्से को, जो कि लाभ कमाने की अंधी दौड़ का हिस्सा है, समूचे पर्यावरण के प्रति असहिष्णु बना दिया है। बीसवीं और यहां तक कि इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने पूंजीवादी विकास का लगभग चरम स्तर प्राप्त कर लिया था। लेकिन अमीरी और शक्ति सम्पन्न होने की भूख इन देशों की नहीं मिटी, जिसका सर्वाधिक नुकसान समूचे विश्व के विकासशील और गरीब देशों को पर्यावरण असंतुलन के रूप में चुकाना पड़ रहा है।चीन और भारत जैसे देशों में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि 'पर्यावारणीय न्याय' का तर्क बेमानी नजर आने लगा है। दुनिया के सर्वाधिक बीस प्रदूषित शहरों में से तेरह शहर भारत के हैं।नदियां इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं उनका पानी किसी भी दृष्टि से पीने योग्य नहीं है। सवाल है कि इस पर्यावरण विनाश के लिए उत्तरदायी कौन है? यह एक तथ्य है कि भारत में संसाधनों के सत्तर फीसद हिस्से पर भारत की एख फीसद आबादी का स्वामित्व है। असल में यही आबादी पर्यावरण विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। यही वह सक्षम आबादी है जो दुनिया की सारी सुविधाओं से संपन्न है। किसानों और आदिवासियों से जमीन खरीद कर समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाली इस आबादी ने उन किसानों व आदिवासियों के सम्मुख जीने का संकट खड़ा कर डाला है। समूचे प्राकृतिक संसाधनों को 'उपभोग की वस्तु' में परिवर्तित कर इन पूंजीवादी वर्ग ने प्राकृतिक संसाधनों को आम जनता की पहुंच से बाहर कर दिया है। परिणामस्वरूप सामुदायिक वस्तु (जैसे मिट्टी, पानी, हवा) जो कि प्रकृति प्रदान किया करती है और पहले जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती थी, अब कीमती वस्तु के रूप में वैश्विक बाजार में खरीदी और बेची जाती है।

यह कैसा विकास है जहां हम तकनीकी ज्ञान के प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, जिसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों के अस्तित्व के लिए दोनों का संरक्षण आवश्यक है। हमने दूसरे राष्ट्रों को मात देने के लिए बड़े-बड़े हथियार और बम बना लिए, दूसरे ग्रहों पर पहुंच गए, पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचने या खरीदारी करने का इंतजाम कर लिया, लेकिन विरोधाभास देखिए कि एक अतिसूक्ष्म वायरस से मुकाबला करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। किसी ने सही कहा है- 'शहरों का सन्नाटा बता रहा है, इंसान ने कुदरत को नाराज बहुत किया है'। ●

लॉकडाउन में रबी फसल का बचाव

मुरलीधर

सरकार ने कृषि गतिविधियों को कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन से बाहर रखकर सही कदम उठाया है। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने किसानों और अन्य अंशधारकों से कहा है कि वे कामकाज के दौरान लोगों से अपेक्षित दूरी बनाए रखें तथा अन्य सावधानियों का पालन करें। कृषि क्षेत्र के लिए यह समय बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस समय रबी की फसल पक रही है। सरकार की कोशिश है कि फसल कटाई सहजता से हो, उसका विपणन और भंडारण भी अच्छी तरह किया जा सके। इस बार असमय बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद गेहूं के उत्पादन का नया रिकॉर्ड कायम होने की आशा है। फसल की समय पर कटाई में किसी भी तरह की चूक से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी अच्छा नहीं होगा।

बहरहाल सरकार के इन प्रयासों के बावजूद किसानों की चिंताएं पूरी तरह दूर नहीं हुई हैं। दरअसल श्रमिकों और ट्रकों की कमी के कारण खेती का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जगहों से मजदूरों का पश्चिमोत्तर भारत के रबी की खेती वाले इलाके में जाना नहीं हो रहा है।

जबकि फसल बुआई और कटाई के मौसम में आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता था। इसके विपरीत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत देश के तमाम शहरी क्षेत्रों के श्रमिक जो आमतौर पर इस समय खेतिहर श्रमिकों की कमी दूर करने इन इलाकों में आ जाते थे, वे भी अब अपने गांवों को लौट चुके हैं। रेल और बस सेवाओं के ठप होने तथा कोरोनावायरस से उत्पन्न भय के कारण निकट भविष्य में श्रमिकों की उपलब्धता संभव नहीं नजर आती।इतना ही नहीं श्रमिकों की कमी दूर करने के लिए खेतों में काम आने वाली मशीनें भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। कंबाइन-हार्वेस्टर ऐसी ही एक मशीन है जिसे किसान किराये पर लेते हैं। आमतौर पर यह मशीन इस समय तक मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में काम करना शुरू कर देती थी क्योंकि वहां फसल जल्दी पकती है। इसके बाद मशीनें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का रुख करती थीं जहां यह काम चल रहा होता। परंतु इस साल इनमें से कई मशीनें मध्य प्रदेश और गुजरात में फंस गई हैं क्योंकि मशीन चलाने वाले तथा उनके हेल्पर नहीं हैं।

बहरहाल, अगर इन सारे हार्वेस्टर को काम पर लगा दिया जाए तो भी वे शायद ही कुल फसल का 50 से 60 फीसदी ही निपटा पाएं। इसके अलावा बड़ी तादाद में ट्रक और अन्य वाणिज्यिक वाहन भी लॉकडाउन के कारण सामान्य रूप से नहीं चल पा रहे। उनमें से कई अनेक दिन से राजमार्गों पर फंसे हैं क्योंकि उन पर लदी वस्तुएं अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी में नहीं थी। अब जबकि कई प्रतिबंध शिथिल किए गए हैं तो हालात में सुधार हो सकता है। हालांकि हालात के पूरी तरह सामान्य होने में समय लग सकता है। इससे कारोबारियों और आधिकारिक खाद्यान्न खरीद एजेंसियों दोनों के सामने माल ढुलाई की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

कृषि बाजारों में भी अभी सामान्य कामकाज शुरू होना बाकी है। दिल्ली की आजादपुर जैसे कुछ बड़े बाजारों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जगह श्रमिक बाजार से आते हैं और वहां इनकी कमी हो गई है। कृषि उपज भंडारण सुविधा भी सीमित है। एफसीआई ने कहा है कि इस बार वह एक अप्रैल के बजाय 15 या 20 अप्रैल के पहले गेहूं खरीद नहीं शुरू कर पाएगा। कुछ कृषक संगठनों ने किसानों को 10,000 रुपये तत्काल देने की मांग की है ताकि उनका काम चल सके। इसे उपज खरीद के बाद समायोजित किया जा सकता है। इन मसलों को जल्द हल करना होगा ताकि रबी फसल की बरबादी न हो। ●

अफ्रीका में कोरोनावायरस के चलते खतरे में हैं 2 करोड़ नौकरियां

अर्थव्यवस्था में आ सकती है 1.1 फीसदी की गिरावट। 35 फीसदी तक कम हो चुका है अफ्रीका का आयात-निर्यात

दुनिया भर में कोरोनावायरस एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इस तरह के खतरों के सामने कितनी कमजोर है। उसका असर दुनिया भर के लोगों के काम धंदे पर दिखने भी लगा है। भारत के कई बड़े शहरों से जहां लाखों-करोड़ों की संख्या में लोग अपनी नौकरियों के छिन जाने की वजह से अपने गावं वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं। वहीं अफ्रीका जो पहले से ही अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। उसपर इस महामारी के चलते चौतरफा मार पड़ने के आसार हैं। हाल ही में अफ्रीकन यूनियन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी के चलते अफ्रीका में करीब 2 करोड़ नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। वहीं बढ़ते कर्ज के चलते आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन और तेल उत्पादन जैसे क्षेत्रों पर आधारित देशों पर इसका सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। महामारी से जुडी दो अलग-अलग संभावनाओं के आधार पर आर्थिक संकट का पूर्वानुमान किया गया है। पहली सम्भावना है कि यह महामारी जुलाई तक अफ्रीका में बनी रहेगी, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरी सम्भावना है कि यह महामारी अगस्त तक ख़त्म नहीं होगी।

कोरोना महामारी : ज्यादा हाथ धोने से भारत में पैदा हो सकता है जलसंकट

पांच व्यक्तियों के एक परिवार को केवल हाथ धोने के लिए प्रतिदिन 100 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि साबुन और पानी से हाथ धोना नॉवेल कोरोनावायरस को हराने का सबसे अच्छा तरीका है और ऐसा किया जाना विश्वभर में फैले कोविड-19 पर नियंत्रण पाने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। हालांकि, देश के विभिन्न शहरों में बसे स्लमों में रहनेवाली गरीब शहरी जनता या वैसे लोग, जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए स्वछता बनाये रखना कोई आसान काम नहीं है। बिना पाइप वाले पानी के घरों में पानी के बर्तन भरने या हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने में ऊर्जा संसाधनों की खपत होती है। इसकी वजह से लोगों में हाथ धोने की आदत विकसित नहीं हो पाती।

चौतरफा आपदा और निपटने के तरीके

पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विषयों पर एक के बाद एक संकट सामने आए हैं। ये इतने व्यापक हैं कि विभिन्न देशों और समुदायों की प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम पड़ सकती है। बता रहे हैं

अरुणाभ घोष

कोविड -19 की महामारी फैलने के पहले ही चालू वर्ष अनिश्चितता के साथ शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के वनों में लगी आग में 1,86,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग जल चुका था। फरवरी में अंटार्कटिका का अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस हो गया जो जलवायु परिवर्तन में गिरावट का स्पष्ट संकेत है। जिंस कीमतों में गिरावट है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग की कमी बनी हुई है और तेल कीमतें भी काफी घट गई हैं। अब हालात और खराब हुए हैं। कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ने के साथ ही शहर, देश और क्षेत्र तक पूरी तरह बंद कर दिए गए। रूस ने तेल उत्पादन में कटौती करने से इनकार कर दिया है। इसके कारण सऊदी अरब ने बाजार में और अधिक तेल की भरमार कर दी और कीमतें लुढ़क गईं। सीमाएं बंद होने और आपूर्ति शृंखला बाधित होने, वस्तुओं और सेवाओं के बाधित होने से लोगों की स्थिति और खराब होने की आशंका है। आर्थिक प्रभाव नजर आने लगा है। डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 11 साल से चल रही तेजी गत सप्ताह समाप्त हो गई। यह झटकों का एक तूफान सा है। पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक संकट का ऐसा सिलसिला जो राज्यों और समुदायों की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को ही संकट में डाल सकता है। कोरोनावायरस ने आर्थिक संकट नहीं पैदा किया, बल्कि जो हालात पहले से खराब थे, इसने उनमें थोड़ा इजाफा किया। वर्ष 2008 में दुनिया का सामना वैश्विक वित्तीय संकट और खाद्य आपूर्ति संकट से एक साथ हुआ। वित्तीय संकट की वजह वित्तीय कुप्रबंधन और जोखिम के संकेतों पर ध्यान नहीं देना थी। खाद्य आपूर्ति संकट के लिए बढ़ती उर्वरक कीमत और ऊर्जा लागत, जैव ईंधन तैयार करने में अनाज का इस्तेमाल और प्रतिकूल मौसम आदि वजहें जवाबदेह थीं। प्रमुख चावल निर्यातक देशों ने निर्यात पर रोक लगा दी। खाद्य कीमतों के झटके ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कमजोर वित्तीय स्थिति वाले देशों को प्रभावित किया। अरब उभार के लिए आंशिक तौर पर यह भी एक वजह था। हम एक बार भी ऐसे ही संयुक्त संकट से गुजर रहे हैं।

ये पृथ्वी के भौतिक जलवायु तंत्र में बदलाव से संबंधित हैं और हमारे पर्यावास से संबंधित हैं जिनके सीमा पार कर जाने पर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है, ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का सिलसिला तेज हो सकता है और समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है। विश्व मौसम संस्थान का अनुमान है कि सन 2030 तक पृथ्वी का तापमान 1.65 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पानी से जुड़ा तनाव सीमा पार तनाव को जन्म दे सकता है। बेमौसम की बारिश या खराब मॉनसून कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मांग में कमी आ सकती है। तेल कीमतों में गिरावट भारत और चीन जैसे बड़े आयातकों के लिए अस्थायी रूप से तेजी का सबब बन सकता है। सरकारों को तय करना होगा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर राजस्व में इजाफा करना है या कम कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को देकर मांग को बढ़ाना है। इस बीच मौसम की अतिरंजना लगातार बढ़ती चली गई। सन 1990 से 2018 के बीच भारत में ऐसी करीब 300 घटनाएं घटीं। इनमें भी अधिकांश घटनाएं वर्ष 2005 के बाद की हैं। सन 1980 के बाद से बाढ़ की घटनाएं तीन गुना बढ़ गई हैं। हम पृथ्वी के साथ क्या करते हैं यह बात बहुत मायने रखती है और पृथ्वी हमारे साथ क्या करती है। परंतु असल बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। व्यापक जन स्वास्थ्य संकट इस बात की अंतदृष्टि प्रदान करता है कि दुनिया को समय-समय पर सामने आने वाले वित्तीय संकट को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, व्यापारिक तनाव से कैसे निपटना चाहिए और जलवायु परिवर्तन के संकट से कैसे निपटना चाहिए।

पहला परिदृश्य: पूरी तरह बंदी। यह सबसे खराब नतीजा है। विभिन्न देश अपने आपको आंतरिक रूप से बंद कर सुरक्षित होने की कोशिश में हैं। वायरस का प्रसार रोकने के लिए यात्राओं पर रोक आवश्यक थी। परंतु सरकार विपरीत आर्थिक प्रभावों से कैसे निपटेगी? यूरोप की सरकारों के पास अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की सीमित गुंजाइश है। अमेरिका ने कई ऐसे उपाय अपनाए हैं जिससे शेयर कीमतें कमजोर हुई हैं। चीन अर्थव्यवस्था को गति देना चाहता है लेकिन उसका निर्यात बाजार बंद है। समायोजित राजकोषीय प्रोत्साहन के अभाव में सरकारें व्यापार संरक्षण का रुख कर सकती हैं। इससे समस्या बढ़ेगी।

दूसरा परिदृश्य: आपातकालीन सेवाएं। यह समयबद्ध प्रतिक्रिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशन के अधीन संसाधनों को ऐसे क्षेत्रों में एकत्रित किया जाता है जहां स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हों। विभिन्न देश ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं साझा करने को तैयार हो गए हैं ताकि गलत सूचनाओं का प्रसार रोका जा सके और जनता का भरोसा मजबूत हो। यदि सन 2020 के मध्य तक वायरस अपने चरम पर पहुंचता है तो सुधार की शुरुआत हो सकती है। परंतु कोई आपदा आर्थिक सुधार को एक और झटका दे सकता है।

तीसरा परिदृश्य: सामुदायिक कदम। जहां खतरा ज्यादा हो वहां छोटे समूहों में बेहतर सहयोग हो सकता है। एक बार जोखिम की सीमा का उल्लंघन हो जाने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मौसम की अतिरंजना भी आशंकाओं को दोबारा जन्म देगी। भारत ने चक्रवातों की अग्रिम चेतावनी देकर और लोगों का जीवन बचाकर अच्छा काम किया है। परंतु केवल सामुदायिक कदमों से आपदा के बाद की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता।

परिदृश्य 4: समेकित कदम। जी 20 देशों के वित्त मंत्रियों, पर्यावरण और स्वास्थ्य मंत्रियों की आपात बैठक के साथ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं चार प्रतिज्ञाएं कर सकती हैं: (1) सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधन की पूलिंग (2) 18 महीनों के व्यापारिक प्रतिबंध पर और प्रतिबंध (3) समन्वित वित्तीय प्रोत्साहन अपनाने होंगे और छोटे कारोबारों की मदद से व्यय शक्ति बढ़ानी होगी (4) अमीर और गरीब देशों के सर्वाधिक संवेदनशील लोगों के लिए जलवायु जोखिम मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया।

मैं एकांत में बैठकर यह लिख रहा हूं। आपात परिस्थितियां हमेशा तार्किक प्रत्युत्तर नहीं पेश करतीं। कई बार ऐसे नतीजे सामने आते हैं जो कम उपयुक्त हों। हमें व्यक्तिगत, संस्थागत और सामुदायिक स्तर पर हल तलाशने होंगे। ●

जिला प्रशासन रांची ने पारस हॉस्पिटल को बनाया कोविड हॉस्पिटल

रांची: वैश्विक महामारी COVID-19 की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन रांची उपायुक्त राय महिमापत रे के नेतृत्व में युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। 31 मार्च को एक COVID-19 पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद से जिला प्रशासन रांची बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। जिला प्रशासन रांची द्वारा पारस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। हॉस्पिटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह से फंक्शनल हो गया है। इस हॉस्पिटल में 50 शैय्या की व्यवस्था है, जहां कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। डॉ जैसमिन एवं डॉ पंकज की देखरेख में यह कोविड हॉस्पिटल कार्य करेगी।

सांसदों, विधायकों मंत्रियों सबका वेतन कटेगा?

केंद्र मे सांसदों के वेतन और निधि में कटौती के साथ ही कोरोना से जंग के लिए राज्यों ने अपने स्तर पर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए वेतन में कमी करने जैसे कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार ने अपने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन का बड़ा हिस्सा स्थगित करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, पेंशनभोगियों को भी तीस फीसद कम पेंशन मिलेगी। महाराष्ट्र में भी मंत्रियों और विधायकों को साठ फीसद कम वेतन मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में भी पचास से पच्चीस फीसद की कमी की गई है। तेलंगाना सरकार भी आइएएस, आइपीएस अधिकारियों को साठ फीसद कम वेतन देगी। राज्य सरकारें ये कदम इसलिए उठा रही हैं, क्योंकि कोरोना पीड़ितों की तादाद बढ़ने का खतरा है। ऐसे में पीड़ितों के इलाज और चिकित्सा कर्मियों के लिए बचाव के जरूरी सामान खरीदे जाने हैं। पूर्ण बंदी की वजह से राज्यों में ठप पड़ गए उद्योग-धंधों को मदद देनी है। वेतन-भत्तों की मद में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में सरकारों के सामने हालात सामान्य होने तक ऐसे कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं रह जाता है।

प्रत्येक गरीब, वंचित, असहाय, पीड़ित तक मदद पहुंचे: हेमन्त सोरेन

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि महामारी की इस घड़ी में प्रत्येक गरीब, वंचित, असहाय, पीड़ित तक सरकारी मदद पहुंचे। यह हम सभी की अहम जिम्मेदारी है। सभी जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि राशन, पेंशन एवं अन्य जरूरी सरकारी मदद समय से जरूरतमंद व्यक्ति को मिले। साथ ही कोरोना से जुड़े सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखा जाये।

रेलवे ने 1250 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया

देश में 21 दिन का लॉक डाउन के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के क्रम में 05.04.2020 को रांची रेल मंडल पर आईआरसीटीसी, वाणिज्य विभाग , रेल सुरक्षा बल,कार्मिक विभाग एवं भारत स्काउट एंड गाइड के सहयोग से निम्नलिखित स्थानों पर लगभग 1250 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया।

झारखंड का व्यक्ति किसी भी राज्य में हो वह भूखा न रहे

◆ **झारखंड सरकार के अनुरोध पर तेलंगाना सरकार ने वहां फसे झारखंड के मजदूरों को दिए 12 किलो चावल और 500 रुपये**

◆ **मुख्यमंत्री दीदी किचन द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाना**

संवाददाता

रांची: राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना संकट में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहना पड़ेगा सरकार इसके लिये कई कदम उठा रही है। सरकार ने ''राज्य स्तरीय कोरोना कंट्रोल रूम'' बनाया है जिसमें लोगों के कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हेतु सम्पर्क करने के लिये 181 टॉल फ्री नम्बर जारी किया गया है। इस टॉल फ्री नम्बर पर 23 मार्च 2020 से लोगों की समस्यायें सुनी जा रही है एवं उसका समाधान भी किया जा रहा है। अबतक 5581 शिकायतें दर्ज किए गए जिसमें 1929 शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है वहीं बचे हुए शिकायतों पर यथा संभव कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त शिकायतों में से स्टेट कंट्रोल रूम में ही 799 मामलो को सुलझा लिया गया एवं लोगों को सही जानकारी एवं सहायता उपलब्ध करा दी गई है। वहीं फूड सप्लाई से संबंधित 1219, चिकित्सा से संबंधित 330, विधि व्यवस्था से संबंधित 197, अन्य राज्यों में फसे लोगों से संबंधित 126 एवं अन्य 57 शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई एवं संबंधित को इस हेतु सहायता पहुँचाया गया है। राज्य सरकार झारखण्ड के सभी लोगों की सुरक्षा के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार झारखण्ड के सभी लोगों की सुरक्षा के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के पास अभी तक सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4729 स्थानों पर झारखंड के 4,55,704 लोगों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है। जिसमें से सरकार द्वारा संबंधित राज्य के आला अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर 4,238 स्थानों पर 2,86,424 लोगों के खाने एवं रहने की व्यवस्था की गई है। झारखंड सरकार के अनुरोध पर तेलंगाना सरकार ने वहां 301 जगह पर फंसे 14,687 झारखंड के मजदूरों के सहयोग हेतु सभी मजदूरों को 12 किलो चावल और 500 रुपये की राशि दिए हैं। सरकार इस ओर हर संभव प्रयास कर रही है कि कोई भी झारखंड का व्यक्ति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो वह भूखा न रहे।

राज्य के सभी जिलों में पीडीएस हेतु खाद्यान्न उपलब्ध कराये गए

झारखंड खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में पीएचएच एवं एएवाई कार्ड धारकों के बीच अप्रैल और मई दोनों माह के अनाजों का वितरण किया जा रहा है जिससे सभी खाता धारकों के पास अनाज की कोई कमी न हो। ज्ञात हो कि प्रत्येक माह पीएचएच कार्ड धारको के बीच, परिवार के प्रत्येक सदस्य हेतु 5 किलो अनाज दिए जाते हैं वही एएवाई कार्ड धारको को प्रत्येक कार्ड पर 35 किलो अनाज दिया जाता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्तनिर्देशानुसार विभाग द्वारा पीएचएच एवं एएवाई कार्ड धारकों के बीच भारत सरकार द्वारा प्राप्त 3 महीने के खाद्यान्नों का वितरण करना है। जिसके तहत दोनों तरह के काड धारकों को 5 किलो प्रत्येक माह के लिए अनाज दिए जाएंगे। राज्य सरकार अप्रैल और मई में 1 किलो की जगह 2 किलो नमक कार्ड धारकों के बीच बांटेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चावल का वितरण किया जाता है वहीं शहरी क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल का वितरण 60 एवं 40% के अनुपात में किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनाज निशुल्क है जबकि राज्य सरकार 1 रुपये प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराती है। भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त है कि 3 माह तक 1 किलो दाल भी दोनों खाता धारकों को उपलब्ध कराया जाए। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में खाद्यान्न उपलब्ध करा दिए गए हैं। विभाग द्वारा अप्रैल माह का शत-प्रतिशत राशन उपलब्ध कराया गया है एवं मई माह का राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मार्च महीने का पी डी एस के तहत लाभुकों तक शतप्रतिशत राशन उपलब्ध कराया जा चुका है वहीं अप्रैल महीने का 32.04% पीडीएस उपलब्ध करा दिया गया है। विभाग द्वारा नन पीडीएस के 112708 लाभुकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए हैं। विभाग द्वारा अभी तक 1,21,477 लोगों तक राशन पहुंचाया जा चुका है।

राज्य के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 344 केंद्र, पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष दाल भात योजना के 472 केंद्र और दाल भात योजना के तहत अतिरिक्त 391 केंद्र कार्य कर रहें हैं जिनपर 10,04,493 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में राहत सामग्रियों के पैकेट का वितरण भी किया जा रहा । 688 गैर सरकारी संस्थाओं एवं वॉलेन्टीयर्स द्वारा भी विभिन्न जिलों में लोगों को खाना खिलाने का कार्य किया जा रहा है ।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में लोगों के बीच हुआ मास्क का वितरण

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आकस्मिक सेवाओं से जुड़े लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। विश्वविद्यालय मुख्यालय में कुलसचिव डॉ नरेंद्र कुदादा ने विश्वविद्यालय कर्मियों, पदाधिकारियों तथा सभी सुरक्षा से जुड़े कर्मियों को मास्क बाँटा। पशु चिकित्सा संकाय में डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद ने डेयरी, पोल्ट्री, सूकर एवं बकरी आदि फार्म के कर्मियों को मास्क प्रदान किया. डॉ प्रसाद ने बताया कि पशुपालन से जुड़े फार्म्स में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी एहतियात बरते जा रहे है। सभी पशु स्वस्थ्य है और उनके चारा का उचित प्रबंध किये गये है।

वानिकी संकाय में नाचेप परियोजना अन्वेंशक डॉ एमएस मल्लिक ने कृषि वानिकी एवं एकीकृत कृषि प्रणाली से जुड़े शोधकर्मी एवं स्नातकोत्तर छात्रों को मास्क बाँटा. डॉ मल्लिक ने बताया कि विश्वविद्यालय की आकस्मिक सेवाओं को गतिशील रखने एवं कर्मियों के कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आईसीएआर एवं वर्ल्ड बैंक की नाचेप परियोजना के तहत करीब 200 विश्वविद्यालय कर्मियों को मास्क दिया गया। मौके पर नियंत्रक राकेश कुमार वर्मा एवं डॉ बीके अग्रवाल भी मौजूद थे।यह जानकारी बीएयू के पीआरओ अजय कुमार ने दी।

अमन यूथ सोसाइटी के सदस्यों का हिंदपीढ़ी में हेल्थ स्क्रीनिंग कैम्प

रांचीः हिंदपीढ़ी में हेल्थ स्क्रीनिंग कैम्प एवं घर-घर जाकर वोलियेन्टर के साथ स्क्रीनिंग का कार्य का किया गया, पूरे हिंदपीढ़ी क्षेत्र में जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा है जिसमे अलग अलग टीम के साथ एक-एक वोलेंटियर साथ में सहयोग कर रहे थे मुख्य रूप से वार्ड संख्या 22 में पूर्व वार्ड पार्षद मो० असलम ने अमन यूथ सोसाइटी के सदस्यों को इस कार्य में लगा कर अपने वार्ड क्षेत्र का स्क्रीनिंग कराने में अपना भरपूर सहयोग स्वास्थ्य कर्मी को प्रदान किया।उन्होंने कहा कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र के सभी सामाजिक कार्यकर्ता अपने स्तर से जिला प्रशासन का सहयोग किये और आगे भी करते रहेंगे, हिंदपीढ़ी वासी सामाजिक कार्य एवं समरसता को बनाने के लिए हमेशा संवेदनशील होकर आगे बढे है,। मो०असलम ने अपने वार्ड के सभी लोगो से अपील किया किया गया कि लॉक डाउन का पालन करे अपने घरों से बाहर न निकले। वार्ड संख्या 5 में करीब 400 परिवारों का स्क्रीनिंग किया गया । मुख्य रूप से निजाम नगर सदर गली,राईन मस्जिद,मक्का मस्जिद,अमन कम्युनिटी हॉल, सहित हिंदपीढ़ी के अन्य गली मोहल्ले में कैम्प लगाया गया।

इस कार्य में सहयोगी के रूप में अफरोज आलम,नदीम इक़बाल, शाहिद अयूबी,मो०राशीद, मो०अकबर मुन्ना, आसिफ हुसैन,जावेद अख्तर,मो०कमाल,शादाब खान,मो०तारिक,मो०मिन्हाज,मो०दिलावर, विलियम टोप्पो,अब्दुल बारीक़,मो० ने सार,मो०हारून,आरिफ जलाल ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, साथ ही साथ वार्ड 22 की पार्षद नाजिया असलम ने हेल्थ स्क्रीनिंग की सफलता के लिए हिंदपीढ़ी के तमाम सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार एवं शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो कार्य महीनो में होता उस कार्य को दो दिनों में करवा कर एक मिसाल कायम कर दिया है इसके लिए हिंदपीढ़ी के जागरूक जनता को भी बधाई की पात्र है। ये जानकारी सोसाइटी के सदस्य नदीम इकबाल ने दी।

खेतों में गेहूं की तैयार फसल कटवाने के लिये प्रधानमंत्री से के. कृष्णमूर्ति ने किया आग्रह

संवाददाता

रांची : आध्यात्मिक/सामाजिक चिन्तक के. कृष्णमूर्ति ने उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों के खेत में तैयार गेहूं की फसल मशीन से कटवाने में सहयोग के लिये प्रधानमंत्री से आग्रह किया है।उन्होंने कहा है कि कोरोना जैसे खतरनाक संक्रमण महामारी के संकट से देश गुजर रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लॉकडाउन से संबंधित दिए गए निर्देश का पालन भारत के लगभग सभी नागरिक सख्ती से पालन कर रहे हैं। इस महामारी महासंकट से 1 सौ 30 करोड़ देशवासियों के प्राण रक्षा के लिए आपके द्वारा ससमय उठाए गए मजबूत व सशक्त कदम के लिए प्रधानमं ी को हृदय से नमन।

आगे उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है। किसानों के खेत में बिल्कुल तैयार गेहूं की फसल खेत से काटने के लिए मजदूर एवं स्वयं किसान भी नहीं निकल रहे हैं। हिम्मत करके वे निकलते भी हैं तो, पुलिस के डंडे पड़ने के डर से पुनः घर के अंदर चले जाते हैं। गेहूं का तैयार फसल नही काटने दी गई तो महामारी से भी अधिक लोग भुखमरी से मरेंगे। इसलिए सरकार और प्रशासन को मध्यम मार्ग अपनाने की जरूरत है। जनता की जरूरतों को भी समझने की जरूरत है। निश्चय ही इस दिशा में सरकार और प्रशासन में विचार चल रहा होगा। राज्य में जल अभाव,

प्राकृतिक आपदा से समय-समय पर फसल नष्ट हो जाने, खाद, बीज, दवा आदि के लिए बैंक व महाजन से लिए गए ऋण समय पर नही लौटा पाने एवं गरीबी जैसी अन्य समस्याओं के कारण पहले से ही अन्नदाता किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसे में कोरोना जैसे महामारी तो, दिहाड़ी करने वाले मजदुर, किसान एवं गरीबों के रोजी-रोजगार बंद हो जाने से जीवन-रक्षा जैसे दूसरी महासंकट के रूप में दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। कोरोना वायरस से चीन को उबरने में करीब 3 महीने से भी ज्यादा समय लग गए। इस अनुभव के आधार पर ऐसा लगता है कि भारत में लगाए गए 21 दिन की लॉकडाउन अवधि आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश के सामने एक दूसरी महान संकट भूखमरी, महामारी की उत्पन्न हो जाएगी। के कृष्णमूर्ति ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यथाशीघ्र (किसान-मजदूर कोरोना रक्षा टीम) जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र, जिला प्रशासन, ग्राम-प्रधान, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्वैच्छिक रूप से सेवा प्रदान करने में रूचि रखने वाले लोगों को लेकर अस्थायी कमिटी का गठन फ़ास्ट ट्रैक गति से करवाया जाय। तत्पश्चात गठित कमिटी के माध्यम से जनपद स्तर पर जितने भी कंपास और कटर मशीन खेतों से गेहूं काटने वाले उपलब्ध है जल्द-जल्द उन सभी की सूची बनवाकर जनपद के प्रत्येक गांव-गांव में भिजवा कर आधे दामों (सब्सिडी) पर गेहूं की फसल कटवाने के लिए कंपास और कटर मशीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ-ही-साथ टीम द्वारा किसानों को पास आवंटित करके उन्हें अनाज, हरी साग-सब्जियों को बाजार/मंडी में बेचने का भी छुट सुनिश्चित कराया जाए।

कृष्णमूर्ति ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देशहित में कई महत्वपूर्ण साहसिक फैसले लिए हैं, उसी तर्ज पर किसान हित के लिए इस महत्वपूर्ण निर्णय एवं आपके द्वारा उठाए गए कदम से राज्य के अन्नदाता किसानों को अतुलनीय सहयोग मिल जायेगा और कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का भी भरपूर पालन होगा। इस महान सहयोग से किसान और मजदूर के घर में जब खाने के लिए अन्न हो जाएगा तो, कोरोना महामारी वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए गांव-गांव के किसान, मजदूर भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देंगे। ऐसा देश के अन्य सभी राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्रियों के माध्यम से यह कार्यक्रम व्यापक रूप से लागु किया जा सकता है।

लॉकडाउनः चालू रहेंगे कृषि मशीनरी, कलपुर्जों की दुकानें, हाईवे पर ट्रकों के गैरेज

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया एक और आदेश

एजेंसियां : कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में जारी लॉकडाउन के बीच खेती-किसानी को लेकर केंद्र सरकार ने कई तरह की छूट प्रदान की है। सरकार चाहती है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। देश में खाद्यान्न की कमी भी नहीं आने पाएं। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कृषि मशीनरी और उनके कलपुर्जों की दुकानें लॉकडाउन के दौरान चालू रखी जा सकेगी। इस छूट में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। हाईवे पर ट्रकों की मरम्मत करने वाले गैरेज और पेट्रोल पंपों को भी चालू किया जा सकेगा, ताकि

कृषि उपज का परिवहन सुगमता से हो सकें। इसी तरह चाय बागानों पर अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी रखते हुए काम किया जा सकेगा।

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा जाएं। बीमारी से बचाव के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। जिला प्रशासन को इस संबंध में निगरानी रखने को कहा गया है।

देवघर जिला के कोरोना राहत कोष में कोई भी दान कर सकते है

संवाददाता :देवघर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैंसी सहाय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला स्तर पर राहत कोष का निर्माण किया गया है। इस राहत कोष का खाता संख्या- 39238814977 एवं IFSC CODE SBIN0000064 एवं शाखा- देवघर है, जिसमे कोई भी दाता अपने इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार दान देकर गरीबों व असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं। उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि देवघर जिला के कोरोना राहत कोष में प्राप्त सहयोग राशि से यहां के असहाय, गरीब, दिव्यांग एवं जरूरतमंद लोगों की मदद की जायेगी एवं उनके बेहतरी के लिए कार्य किया जायेगा। इस प्रकार के कार्य में समाज के सभी वर्ग के लोगों का सहयोग आपेक्षित होता है, क्योंकि सभी के सहयोग से हीं किसी भी अच्छे कार्य को फलीभूत किया जा सकता है।

सब्जी और फूल के किसानों की स्थिति खराब

एजेंसियां :तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले के होसुर ब्लॉक के एक किसान नेता टी कोदंडारामन सब्जी और फूल किसानों की स्थिति को लेकर परेशान हैं। ज्यादातर सब्जियों का उत्पादन कर्नाटक पहुंचने वाली अधिकतर सब्जियों का उत्पादन होसुर में होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसान सब्जियों को लेकर कर्नाटक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फूल की खेती करने वाले किसानों की भी यही हालत है, क्योंकि वेंडर्स ने फूल खरीदना बंद कर दिया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि लॉकडाउन की घोषणा में आवश्यक सामान जैसे फल, अनाज और सब्जियों को ले जाने की अनुमति दी गई है।

फसल तैयार है लेकिन काटने के लिए मजदूर नहीं

◆ **किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना लॉकडाउन**

राजन कुमार

तमाम एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया को बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से देश-दुनिया को आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस का गंभीर परिणाम देश के किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। गांवों की हालत ऐसी हो गई है कि ग्वाला लोगों से दूध नहीं खरीद रहा है, क्योंकि मिठाई की दुकानें बंद होने से दूध की सप्लाई नहीं हो रही है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन का खामियाजा उन किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है जिनकी पूरी खेती ही मजदूरों के भरोसे है।

24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद बढ़ी मुसीबत

24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके बाद जो जहां पर था, वहीं अटक गया। कुछ लोगों ने पैदल और रिक्शा से पलायन भी किया। 27 मार्च को लॉकडाउन के नियमों में संशोधन हुआ और कृषि कार्य को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल

किया गया, लेकिन शायद संशोधन करने में सरकार की ओर से देरी हो गई। इसी बीच दिल्ली, पंजाब, मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में मजदूरी कर रहे मजदूर घबरा गए और गांव के लिए पलायन कर गए।

मजदूरों के इस पलायन का सबसे बड़ा नुकसान पंजाब के उन किसानों को हो रहा है जिनकी खेती बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों के भरोसे थी। इस वक्त गेहूं की फसलें पक गई हैं और उन्हें काटने का वक्त निकला जा रहा है लेकिन मजदूरों की कमी के कारण फसल खेत में बर्बाद हो रही है। इसी बीच मौसम का भी डर है, क्योंकि यदि खुदा-ना-खास्ता मौसम का मिजाज बदला और आंधी-तूफान के साथ बारिश हो गई और ओले गिर गए तो किसानों पर आफत का पहाड़ टूट जाएगा।

कृषि गतिविधियों में छूट की बात सिर्फ कहने की रह गयी

27 मार्च के आदेश में लॉकडाउन से मुक्त होने वाली गतिविधियों में फसल की कटाई, कटाई की गई फसल की बाजार में आवाजाही, कस्टम हायरिंग केंद्र जो कि हार्वेस्टर और ट्रैक्टर जैसी मशीनरी किराए पर देते हैं और खाद, बीज और कीटनाशकों का निर्माण करते हैं शामिल हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव विजू कृष्णन के मुताबिक गेहूं और धान जैसी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए अब कटनी की फसल को मंडियों में ले जाने को लेकर समस्या है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में कृषि गतिविधियों को छूट की बात सिर्फ कहने की है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अनाज और अन्य फसल सीधे खेत से उठाकर सरकार द्वारा मंडी में पहुंचाया जाए।

इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर शुदा नारायणन ने कहा कि केंद्र के आदेश में राज्यों के साथ समन्वय की कमी नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना को ले सकते हैं। तेलंगाना ने किसानों को मंडी में जाने के लिए एक टोकन प्रणाली का इंतजाम किया है। इसके अलावा राज्य ने फसल की खरीद में पूर्ण विकेंद्रीकरण का वादा किया है, जिसके तहत फसल की खरीदी प्रत्येक गांव में संबंधित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम हो रही है। नारायणन ने कहा कि ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में पहले से ही विकेंद्रीकृत खरीद नियम लागू है। ऐसे में वहां किसानों को परेशानियों का कम सामना करना पड़ रहा है। ●

महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही सरकार, जानिए कैसे मिलेगी रकम

शशिभूषण

रांची : बीते कुछ समय से कोरोना वायरस की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं। यही वजह है कि बीते दिनों पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1।70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया।

इसके दायरे में आने वाली करीब 20 करोड़ महिलाओं को सरकार जनधन बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है। हर महिला के बैंक खाते में प्रति मांह 500 रुपये आएंगे। मतलब ये कि तीन महीने में सरकार कुल 1500 रुपये खाते में डालेगी। हालांकि, हर किसी को एकसाथ पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। जिन जनधन महिला खाताधाकों की खाता संख्या का अंतिम अंक 0 और 1 है, उन्हें उनके खाते में तीन अप्रैल को पैसा आ चुका है। वहीं खाते के अंत में संख्या 2-3 वाले खाताधारकों के खाते में चार अप्रैल को राशि डाली गई है। इसके बाद साप्ताहिक अवकाश की वजह से बैंक बंद हैं।वहीं जिन लाभार्थियों की खाता संख्या 4-5 है, उनके खातों में सात अप्रैल को पैसा डाल दिया जाएगा। इसके अलावा जिन खाताधारकों के खाते की संख्या के अंत में 6 या 7 है, उनके खाते में अगले दिन यानी आठ अप्रैल को यह राशि डाल दी जाएगी।आखिरी किस्त 8 और 9 नंबर अंक वाले खाताधारकों के खाते में नौ अप्रैल को डाली जाएगी। ऐसे में आप अपने खाते का आखिरी नंबर देखकर ही पैसे निकालने के लिए जाएं।।

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी ट्वीट कर खाते में पैसे ट्रांसफर करने की तारीख का डिटेल दिया है।

फोटो न्यूज

तस्वीर बुढमू के बन्द पड़े छापर कोलयरी की है । जहां लॉकडाउन का फायदा उठाकर कोयले की अवैध खुदाई हो रही थी। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों का कहना है कि रात होते ही दर्जनों लोग अंद पड़े इस खदान से कोयला निकालने में लग जाते थे। अंततः खदान धंस गया । सीसीएल का स्विच रूम हूआ ध्वस्त हो गया। जमीनदोज होने से कई घर बाल बाल बचे । गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गयी। और बड़ा हादसा टल गया। अब यहां जमीन फट कर बड़ी बड़ी हुई दरारें हो गयी हैं। फोटो : उज्ज्वल

योगः तन और मन का व्यायाम

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

योग संस्कृत शब्द युज से निकला है जिसका मतलब है जुड़ना या एकता ।योगा सही तरीके से जीने का विज्ञान है।योगा तन और मन का व्यायाम है अगर आप कोई और व्यायाम करते है तो ये सिर्फ आपके शारीरिक बल को बढाता है परन्तु योगा शारीरिक बल के साथ आपको शांत रखता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति को प्रबल बनाए रखता है।

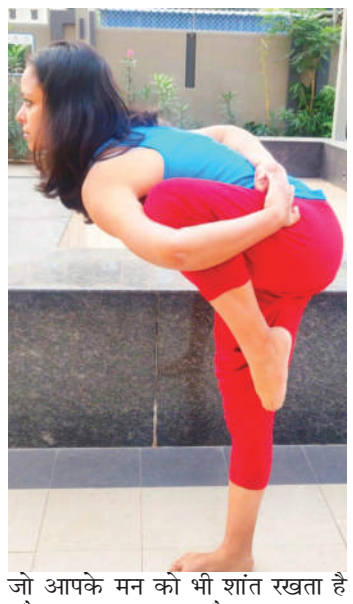

जो आपके मन को भी शांत रखता है और तनाव कम करता है

● वजन में कमी - नियमित योगासन करने से जहां शरीर मजबूत होता है , मांस पेशियों को टोन करता है वहीं वजन कम करने में भी सहायक है।

●तनाव टूर करता है - योगा करने से शरीर से अच्छे हारमोन रिलीज़ होते है

●ऊर्जा में वृद्धि- रोज की भागदौड़ भरी दिनचर्या में हम काफी थक जाते है परंतु रोजाना योगा अभ्यास करने से हमारी ऊर्जा में वृद्धि होती है।

● बेहतर लचीलापन - योगा शारीर के लचीलापन को बढ़ाता है जो शरीर की टूट फूट से रक्षा करता है।

● सम्पूर्ण स्वस्थ की रक्षा- रोजाना अभ्यास से सम्पूर्ण स्वस्थ की रक्षा होती है ये अंदर से आपको मजबूत बनता है और रोगो से लड़ने में सहायक है।

●ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल- योगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है । डायबिटीज ,ब्लड प्रेशर, थायरायड जैसे बीमारियों को कंट्रोल करने से सहायक है।

जब योगा के इतने सारे फायदे है तो आज ही से करो योग और रहो निरोग।

इम्यून सिस्टम को बढाता है विटामिन सी

कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया ग्रस्त है। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। बचाव करना है तो हमें कुछ सावधानियां और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करना होगा। *विटामिन सी* से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन इम्यूनिटी को मजबूत करने में काफी मददगार होता है। *विटामिन सी* शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ता और मौसम में बदलाव या हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से भी बचाव करने में मदद करता है। कुछ फल और सब्जियां जो विटामिन सी से भरपूर हैं जैसेः

आंवला	कीवी
संतरा	टमाटर
नींबू।	फूलगोभी
स्ट्रॉबेरी	अमरूद
ब्रोकली।	शिमला मिर्च
पत्तागोभी।	मौसमी

विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और कोशिकाओं को भी क्षतिग्रस्त होने से बचाता है और बाल दांत , त्वचा , मसूड़े , आंखो को भी स्वस्थ रखने में भी मदद करता है।

इम्युनिटी बढ़ाने के तरीके : ◆ कोशिश करें कि दिनभर में जितनी बार भी पानी पीएं, उसे हल्का गर्म करके ही पीएं। खासतौर पर ठंडे पानी से फिलहाल परहेज करें। क्योंकि बदलते मौसम में ये आपको बीमार बना सकता है। ◆ रोज कम से कम 30 मिनट का समय सिर्फ अपने लिए निकालें। इस बीच योगासन, प्राणायाम और ध्यान लगाएं। परिवार के साथ रहते हैं, तो घर के अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए कहें। इससे तन और मन दोनों तंदुरुस्त होगा।◆इन दिनों आप जो भी खाना खा रहे हों, कोशिश करें कि उसमें हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का इस्तेमाल जरूर हो। ज्यादा तेल, बटर वाले खाने से परहेज करें।◆च्यवनप्राश का एक डब्बा ले आएं। रोज सुबह उठकर फ्रेश होकर एक चम्मच (करीब 10 ग्राम) च्यवनप्राश जरूर खाएं। घर के हर सदस्य को रोजाना एक चम्मच च्यवनप्राश खाने के लिए दें।◆ दिन में कम से कम एक या दो बार हर्बल चाय / काढ़ा पीएं। यहां समझें कि काढ़ा कैसे बनाना है – पानी में में तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक, मुनक्का मिलाकर अच्छी तरह धीमी आंच पर उबालें। स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं।◆ दिन में कम से कम एक या दो बार हल्दी वाला दूध पीएं। 150 मिली लीटर गर्म दूध में करीब आधी छोटी चम्मच हल्दी मिलाकर पीएं।◆ नैजल एप्लीकेशन : रोज सुबह और शाम नाक के दोनों छिद्रों में तिल का तेल या नारियल का तेल या घी लगाएं। ध्यान रहे इसकी मात्रा बहुत ज्यादा न हो।◆ ऑयल पुलिंग थेरेपी : एक बड़ी चम्मच तिल का तेल या नारियल का तेल मुंह में लें। ध्यान रहे इसे पीना / गटकना नहीं है। इसे दो से तीन मिनट के लिए मुंह में घुमाएं और फिर थूक दें। फिर हल्के गर्म पानी से कुल्ला कर लें। ये प्रक्रिया दिन में एक या दो बार की जा सकती है।

94 फीसदी तक वायरसों का सफाया करते है समुद्री जीव

एजेंसियां :एक अध्ययन में पता चला है कि समुद्री जीव वायरसों को आसानी से निपटा देते हैं। विभिन्न प्रकार के समुद्री जानवर ऑक्सीजन और भोजन के लिए समुद्री जल को छानते हुए वायरस के अणुओं का सफाया कर सकते हैं। अध्ययन की अगुवाई कर रही रॉयल नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर सी रिसर्च के जेनिफर वेल्श कहती हैं कि जब एक वायरस किसी कोशिका को संक्रमित करता है, तब यह नए वायरस को बनाने के लिए होस्ट का उपयोग करता है। इस–के बाद वे कई और नई कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन वेल्श ने पाया कि समुद्र के एक गिलास पानी में 15 करोड़ से अधिक वायरस के अणु पाए जाते हैं। समुद्री जानवर इन वायरस के अणुओं को भोजन के रूप में खाकर समाप्त कर सकते हैं।उदाहरण के लिए, जापानी सीप समुद्री पानी को छानकर ऑक्सीजन या भोजन जैसे कि शैवाल और बैक्टीरिया को अलग कर देता है। ऐसा करते समय, यह वायरस के अणुओं को निगल जाता है। वेल्श ने कहा कि हमारे प्रयोगों के दौरान हमने सीपों को कोई भोजन नहीं दिया और इसलिए उन्होंने केवल ऑक्सीजन के लिए पानी को फिल्टर किया।

कोरोना के डर से शहर छोड़ कर गांव की ओर जा रहे हैं अमेरिकी

एजेंसियां : कोरोना लॉकडाउन की खबर आने के बाद भारत में लाखों दिहाड़ी मजदूर अपने गांव की ओर निकल पड़े. लेकिन दुनिया के सबसे संपन्न देश कहे जाने वाले अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है?

प्रतीकात्मक फोटो

इन दिनों अमेरिका में ज्यादातर लोग खाने पीने का सामान जमा करने में लगे हैं. सुपरमार्केट में जिस जिस सामान की कमी हो रही है, उसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है. लेकिन इसके साथ साथ एक और बिजनेस भी फायदे में दिख रहा है, रियल एस्टेट का. फॉर्टीट्यूड रैंच जैसी कुछ कंपनियां लोगों को यह कह कर लुभा रही हैं कि वे उन्हें ऐसे दूर दराज के इलाकों में घर दिलाएंगी जहां उन्हें कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी. इसे "सर्वाइवल कम्यूनिटी" का नाम भी दिया गया है. कंपनी का नारा है, "बुरे वक्त की तैयारी के साथ वर्तमान का आनंद लें."कंपनी के सीईओ इर्यू मिलर का कहना है कि कोरोना संकट के बीच उनकी प्रॉपर्टी में रुचि दिखाने वालों की संख्या दस गुना बढ़ गई है. थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से बात करते हुए उन्होंने बताया, "लोगों को डर है कि अगर वायरस और घातक साबित हुआ या क्वॉरंटीन से फायदा नहीं हुआ और ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, तो खाने की चीजों पर और न्याय व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा." ऐसे में कंपनी इन घरों में अंडरग्राउंड बंकर देने का भी वादा करती है जो कथित रूप से न्यूक्लियर हमले से भी बचा सकेंगे. साथ ही इन घरों में पहले से खाने पीने का खूब सामान भरा गया होगा. मिलर का कहना है कि इन घरों को यह सोच कर बनाया गया है कि "जब सामाजिक व्यवस्था ठीक से काम करना बंद कर देगी, चारों तरफ लूट मची होगी, कानून व्यवस्था का कोई अता पता नहीं होगा और शहर स–रक्षित नहीं रह जाएंगे" तब लोगों को एक सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया जा सकेगा. अमेरिका में इस बीच कोरोना संक्रमण के दो लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. दुनिया में और किसी भी देश में इतने मामले नहीं देखे गए हैं. भीड़भाड़ वाले शहरों जैसे कि न्यूयॉर्क पर सबसे बुरा असर पड़ा है. ऐसे में कुछ लोग सुरक्षित रहने के लिए शहरों से भागने की सोच रहे हैं. लेकिन जानकारों का मानना है कि भीड़ से दूर गांव देहात में रहना और भी जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि जरूरत पड़ने पर वहां चिकित्सीय सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंचाई जा सकेंगी.

क्या पीजन पॉक्स बीमारी से मर रहे हैं कबूतर?

देवाशीष

रांची : पिछले महिने रांची के बिरसा जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू का मामला आया था। इससे जू के दस पक्षी मर गये थे। इस वाकये के बाद बिहार में भी कई जिलों में पक्षियों के मरने की घटनायें देखी गयीं। जानकारों ने इसे बर्ड फ्लू से जोड़ कर देखा। बुंडू में भी बगुलों के मरने पर ग्रामीण भयभीत थे उन्हें अपने पोल्ट्री उघोग की चिंता सताने लगी थी। पशु चिकित्सकों का भी ये मानना है कि बर्ड फ्लू की उपस्थिति क-हीं न कही हैं। इस बीच कोरोना के संकट में बर्ड फ्लू की चिंता क-हीं खो गयी। लेकिन रांची में हाल में फिर से कई जगहों पर पक्षियों के मौत से बर्ड फ्लू की चिंता फिर से उभर आयी। कुछ लोगों ने लॉकडाउन में पक्षियों के मरने पर ये कयास लगाये कि इस बंदी में इन पक्षियों को दाना नहीं मिल पा रहा होगा इस लिये भूख से इनकी मौत हुई होगी? लेकिन हाल के दो दिनों में कुछ लोगों का कहना है कि छत पर दाना और पानी देने के बावजूद कबूतरों की मौत रही है। पर्यावरणविद् नितिश प्रियदर्शी ने भी किसी रोग की ओर इशारा किया है । कुछ मृत कबूतरों के सिर में दाने निकलने पर पशु चिकित्सकों का कहना है कि ये पीजन पॉक्स से मर रहे हैं।और ये रोग कबूतरों से अन्य पक्षियों में भी फैल सकता है। अब इसकी जांच के लिये कबूतरों को सैंपल कोलकाता भेजा गया है।

याद आते हैं पर्यावरण प्रेमी स्व. केशव लाल महतो

सिदाम महतो

रांची/बुण्डूः कुछ लोगों का जीवन सफर लम्बा तो नही होता है पर उनके पड़ाव को लम्बे समय तक याद किया जाता है।हम याद कर रह हैं स्व.केशव लाल महतो को ,जिनका जन्म बुंडू प्रखण्ड अंतर्गत एड़केया गांव में 3 मार्च 1969 ई को हुआ था। ग्रामीण विकास से जुड़े कई संस्था में काम किए। जीवन भर समाज सेवा से जुड़े रहे।31 मार्च 2014 ई को जमशेदपुर में एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। 45 वर्ष की उम्र में वे दुनिया छोड़ कर चले गए, यहाँ उनकी यादें रह गयी।

केशव दा साफ-सफाई के प्रति बहुत ध्यान देते थे।स्वच्छ भारत अभियान से बहुत पहले अपने गांव के बच्चों को गली- मोहल्ला साफ रखना सिखाया।पर्व त्यौहार के मौके पर उनके गांव के सड़कों की सफाई उनके ही मार्गदर्शन में होती थी।आज भी उनके बताए मार्ग पर गांव की युवा पीढ़ी चलने का प्रयास करती है। मकर संक्रांति पर्व के मौके पर सड़कों की साफ-सफाई उनके गांव में आज भी की जाती है। केशव दा पर्यावरण के प्रति बेहद लगाव रखते थे।उनके गांव से होकर कांची नदी गुजरती है।नदी की धार से मिट्टी कटाव से वे चिंतित रहते थे।मिट्टी कटाव से उनके गांव के किसानों की कई एकड़ जमीन नदी में बह गयी।नदी किनारे होकर एक रास्ता गुजरती थी जिससे होकर

लोग नेशनल हाईवे तक पहुंचते थे वो रास्ता भी प्रभावित हुई। सड़क किनारे गहरी खाई बन गई थी। उस जगह कोई दुर्घटना न हो इसलिए वहां लाल झण्डा भी गाड़ देते थे। नदी किनारे के मिट्टी की ढलान पर कुछ पौधे रोप दिए थे। उससे भी मिट्टी कटाव में कमी आई। हालाँकि सरकार के प्रयास से नदी किनारे में बनी गहरी खाई को मिट्टी से भरा गया। कटाव को रोकने के लिए तार की जाली में पत्थर भर कर गार्ड वाल बनाया गया।पर केशव लाल महतो के गिलहरी सा प्रयास को याद किया जाता है।

केशव दा बच्चों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते थे। गांव के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से स्कूल के प्रांगण में फूल के पौधे भी लगवाते थे।बच्चे समय का सदुपयोग करें इसका भी वे आग्रह करते थे।छुट्टी के दिनों में दोपहर में बच्चे घरवालों की नजर से बचकर खेलने निकल जाते थे। पर केशव दा की नजर से बच नही पाते थे।वे दोपहर को खेलने से मना करते,पढ़ने के लिए कहते थे। गांव के कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने में मदद की। उनके ही प्रयास से गांव के युवा रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची द्वारा संचलित रोजगार ट्रेनिंग में भाग ले पाए। लगभग 20 वर्ष पहले केशव लाल महतो ने अपने गांव में खुद की जमीन पर सागवन के लगभग सौ पौधे लगा दिए। पौधे आज बड़े होकर वृक्ष का रूप ले लिए हैं। बाजार में उन पेड़ों की कीमत लाखों में हो सकती है। पर केशव दा के प्रयास से सागवन का वह बगीचा पंछियों के रुकने का पड़ाव बना। वहां से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है, प्राण वायु आक्सीजन मिल रहा है।ये उपहार अमूल्य है।

लॉकडाउन के कारण गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया सुधार

उज्मी अतहर

कोरोनावायरस महामारी की वजह से देशभर में लॉकडाउन (बंद) के बाद से गंगा नदी की स्वच्छता में बड़ा सुधार देखा गया है क्योंकि इसमें औद्योगिक इकाइयों का कचरा गिरने में कमी आई है। विशेषज्ञों ने यह बात कही है। भारत में कोरोना वायरस के कारण तीन हफ्तों का बंद है। लॉकडाउन की वजह से 24 मार्च से ही देश की 1.3 अरब आबादी घरों में ही सिमटी हुयी रही है।

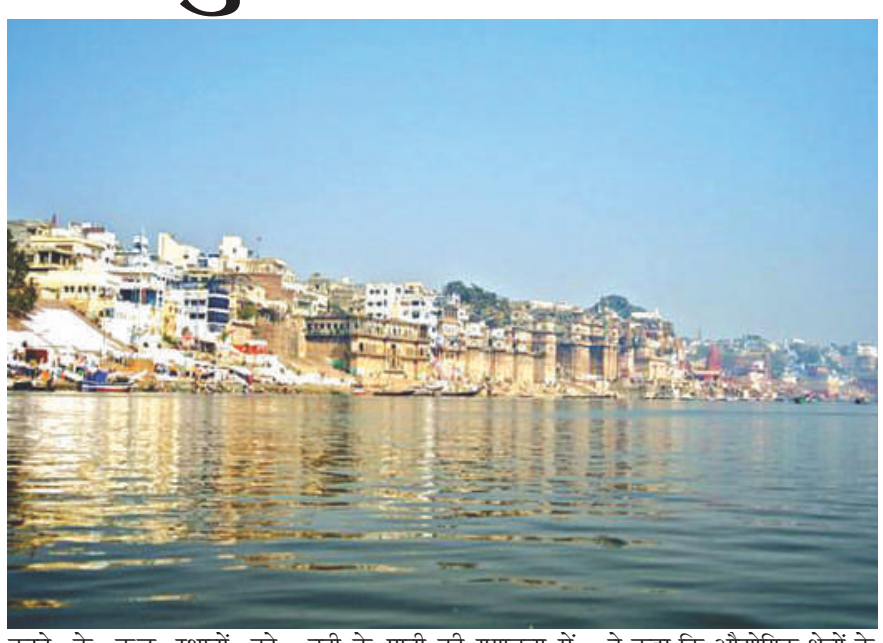

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, ज्यादातर निगरानी केंद्रों में गंगा नदी के पानी को नहाने लायक पाया गया है। सीपीसीबी के वास्तविक समय के निगरानी आंकड़ों के अनुसार, गंगा नदी के विभिन्न बिन्दुओं पर स्थित 36 निगरानी इकाइयों में करीब 27 बिन्दुओं पर पानी की गुणवत्ता नहाने और वन्यजीव तथा मत्स्य पालन के अनुकूल पाई गई। इससे पहले, उत्तराखंड और नदी के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के कुछ स्थानों को छोड़कर नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरने तक पूरे रास्ते नहाने के लिए अनुपयुक्त पाया गया था। विशेषज्ञों ने कहा कि खासतौर से औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास बंद लागू होने से गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पर्यावरणविद् मनोज मिश्रा ने कहा कि सीपीसीबी के लिए उद्योगों से हो रहे प्रदूषण के स्तर का अध्ययन करने का यह बहुत सही समय है। पर्यावरणविद् विक्रांत तोंगड ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार देखा गया है। तोंगड ने कहा कि औद्योगिक शहर कानपुर में गंगा के आसपास काफी सुधार देखा गया है जहां से बड़ी मात्रा में औद्योगिक कचरा निकलता है और इसे नदियों में फेंका जाता है। उन्होंने कहा, ''गंगा की सहायक नदियों जैसे कि हिंडन और यमुना में भी पानी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है।'' उन्होंने बताया कि इस बंद की अवधि के आने वाले दिनों में गंगा के पानी की गुणवत्ता में और सुधार होने की संभावना है।

पर्यावरणविद् और साउथ एशिया नेटवर्क ऑफ डैम्स, रिवर्स, पीपुल्स (एसएएनड-ीआरपी) के सहायक समन्वयक भीम सिंह रावत ने कहा कि मथुरा के आसपास गंगा में भी सुधार देखा गया है। उन्होंने कहा, ''नदी में अब भी जैविक प्रदूषण है लेकिन उद्योगों के रासायनिक प्रदूषण ने नदी के खुद से साफ करने वाले तत्वों को नष्ट कर दिया। खुद से साफ करने के तत्वों में सुधार के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।'' हालांकि, गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। ●

1.5 करोड़ मुर्गियों को मारने के लिए मांगी इजाजत

दाना नहीं मिलने से जींद और बरवाला में मुर्गियां मरने लगी है, व्यापारियों की चिंता बढी

एजेंसियां :कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देशभर में किए गए 21 दिन का लॉक-डाउन हरियाणा की पॉल्ट्री फार्म पर भारी पड़ रहा है। अब पॉल्ट्री फार्म संचालकों को मुर्गियों के खाने के लिए दाना नहीं मिल रहा है। जिसकी वजह से पॉल्ट्री फार्म मालिकों ने अब मुर्गियों को मारने का निर्णय लिया है। जींद और पंचकूला के बरवाला तहसील के कई पॉल्ट्री फार्म में भूख के कारण मुर्गियों की मौत भी हो गई है। हरियाणा पॉल्ट्री फॉर्म एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर करीब डेढ़ करोड़ मुर्गियों को मारने की अनुमति मांगी है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पहले चिकन से कोरोना फैलने की अफवाह से कारोबार ठप है और अब लॉकडाउन की वजह से मुर्गियों के लिए दाना नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह भूखे से मर जाएगी। इससे महामारी का खतरा अलग फैलेगा। इसलिए सभी पॉल्ट्री फार्म एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर सरकार से मुर्गियों को मारने की अनुमति मांगी है।

E ZONE CARE

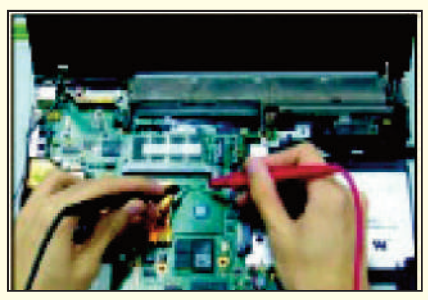

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।